CHETANA
International Journal of Education
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2022 = 6.261
आलेख
Received 18.11.2022 Reviewed 22.11.2022 Accepted 28.11.2022

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं अध्यापक शिक्षा में पैराडायम शिफ्ट:समस्याएं एवं संभावनाएं

* *डॉ संजय कुमार*

मुख्य शब्द : *शिक्षा नीति, अध्यापक शिक्षा, पैराडायम शिफ्ट आदि.*

सारांश

आखिर पैराडायम शिफ्ट है क्या? –वास्तव में इसका संबंध ज्ञान- विज्ञान में सिधांत एवं व्यवहारों के नवीन परिवर्तनों से है जो प्रक्रिया को व्यापक रूप में प्रभावित करती है । वास्तव में हम आज अध्यापक शिक्षा में नए पैराडायम शिफ्ट की बात इसलिए कर रहें हैं क्योंकि हाल के वर्षों में अध्यापक शिक्षा के स्वरुप में व्यापक बदलाव आया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अलोक में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है । अध्यापक शिक्षा हमेशा से किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य अंग रहा है क्योंकि बच्चों के शिक्षण-अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षकों का ही होता है । साथ ही अध्यापक शिक्षा संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया से भी नजदीकी रुप से जुड़ा होता है । देश में अध्यापक शिक्षा के हजारों केंद्र होने के बावजूद गुणात्मक रूप से शिक्षकों के निर्माण की समस्या आज भी महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है । यही कारण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा में व्यापक बदलाव का सृजन करेगा ।

परिचय

शिक्षक शिक्षा की संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रकृति पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण ने शिक्षाविदों में दो प्रकार की बहस को जन्म दिया है - 1, क्या ऐसे संस्थान, जहां केवल शिक्षक प्रशिक्षण किया जाता है, अंतरविषययक और एकीकृत नहीं होने के कारण बंद हो जाएंगे, 2. क्या बदली हुई शिक्षक शिक्षा प्रणाली शिक्षक शिक्षा की वर्तमान चुनौतियों से पार पाने में सक्षम होगी? इस संदर्भ में, शिक्षाविद में दो मत है –पहला बी.एड. कॉलेज जैसे स्टैंड अलोन संस्थानों को बंद करना उचित कदम होगा। ये शिक्षाविद महाविद्यालयों या अपेक्षित परिवर्तनों में व्यापक संभावनाएं तलाश करते दिखलाई पड़ते हैं । दूसरा – क्या नवीन परिवर्तनों से शिक्षक शिक्षा के बुनयादी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी या नए बदलाव के साथ नई चुनौतियों की

स्थिति में अध्यापक शिक्षा से जुड़ी समस्याएं यथावत बनी रहेगी। यह आलेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में अध्यापक शिक्षा में पैराडायम शिफ्ट, इसकी समस्याओं एवं संभावनाओं पर एक दृष्टि प्रदान करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा *संबंधी प्रमुख प्रावधान*

नई शिक्षा नीति कहती है कि अध्यापक शिक्षा बहुविषयक एवं व्यापक **(multidisciplinary and Comprehensive process)** है । और शिक्षण प्रक्रिया में नए बदलाव के साथ साथ अध्यापकों को निम्न पहलूवों में जागरूक होना जरुरी है –भारतीय मूल्य, भाषा, ज्ञान , लोकाचार, परम्पराएँ एवं जनजातीय संस्कृति । इस नीति में जस्टिस जे.एस.वर्मा आयोग, 2012 रिपोर्ट के हवाले यह चिंता भी जाहिर की गयी है कि स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टिट्यूसन जिनकी संख्या लगभग 10 हज़ार है महज डिग्री बेचने वाली संस्थाएं बन कर रह गयी है । अतः इस सेक्टर को **एकीकृत (INTIGRATE), विश्वसनीय(RELIABLE) , प्रभावी (EFFECTIVE) एवं उच्च गुणवता का (HIGH QUALITY) का बनाना जरुरी है I** नई शिक्षा नीति कहती है कि स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टिट्यूसन अगर नए मापदंडों पर खरे नही उतरते हैं तो साल भर का समय देकर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी और नए नीति के अनुरूप केवल 2030 तक अकादमिक रूप से सक्षम , बहुआयामी और एकीकृत (Academically Sound, Multidisciplinary and Integrated) बीएड. कोर्स ही चलेगें । शेष बंद कर दिया जाएगा । अर्थात चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.एड.पाठ्यक्रम चलेगा । नई शिक्षा नीति के अनुसार चुकी अध्यापक शिक्षा के लिए एक समग्र एवं बहुविषयक संसथान का होना जरुरी है इसलिए कोर्स **विश्वविद्यालय या बहुविषयक विश्वविद्यालय** में विभाग स्थापित कर चलना चाहिए । यह नीति यह भी कहती है कि ऐसे मेधावी छात्र जो पहले से स्नातक की डिग्री हाशिल कर चुके हैं उनके लिए **दो वर्षीय बी.एड.,** जो चार वर्षीय स्नातक किये है उनके लिए **एक वर्षीय बी.एड.** का कार्यक्रम भी चल सकेगा । आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए स्कालरशिप भी दी जाएगी Iइस कार्यक्रम में नवीन मापदडों के अनुरूप विभिन विषयों के शिक्षक नियुक्त किए जाएगें जिनमें शोध कार्यों की प्राथमिकता दी जाएगी । शिक्षक प्रशिक्षण को गुणात्मक, प्रभावी एवं उपयोगी बनाने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी एवा निजी विद्यालयों का एक नेटवर्क तैयार होगा जो सहसंबंधित हो कर प्रशिक्षण क्रियाकलापों में भाग लेगें शिक्षा संकाय के सदस्यों में शैक्षिक विविधता होगी साथ ही पी.एच.डी. करने वाले छात्रों को अनिवार्य रूप से शिक्षा के बुनयादी मसलों पर जैसे –**एजुकेशनल प्रोसेस, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, इवैल्यूएशन सिस्टम एवं कम्युनिकेशन का अनुभव** प्रदान किया जायेगा । सलाह अर्थात मेटरिंग के लिए विशेषज्ञों के निर्देशन में एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा ।

अध्यापक शिक्षा - क्या है भविष्य की संभावनाएं? (Future Prospects)

एकीकृत (INTIGRATE), विश्वसनीय(RELIABLE) , प्रभावी (EFFECTIVE) एवं उच्च गुणवता का (HIGH QUALITY) अध्यापक शिक्षा बढ़ेगा । विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा संकायों की स्थापना होगी एवं अध्यापक शिक्षा के लिए उच्च गुणवता वाले शैक्षिक संस्थानों की संख्या बढ़ेगी । अवसंरचना में सुधार के साथ साथ संसाधनों में वृधि होगी । शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक शोध एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा । स्टैंड अलोन संस्थान जो मानको पर खरे नहीं उतरेगें उन्हें बंद कर दिया जाएगा । अध्यापकों की जो नई टीम तैयार होगी वह कौशल से परिपूर्ण होने के साथ साथ विभिन्न विषयों के जानकर एवं भारतीय परम्परा एवं मूल्यों की जानकारी होगी । पहले के तुलना में अधिक **रिलाएबल, सस्टेनेबल, अकाउंटएबल** अध्यापक शिक्षा व्यवस्था विकसित हो पाएगी ।

अध्यापक शिक्षा की मौजूदा समस्याएं –

- इंफ्रास्ट्रक्चर की घोर कमी: अधिकांश सरकारी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में अवसंरचना की घोर कमी है, अधिकांश प्रदेशों में यह कोर्स सामान्य कोर्स के भवनों में संचालित हो रहा है.
- सरकारी बनाम प्राइवेट का द्वन्द : अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राइवेट संस्थानों की बहुलता है, अधिकांश प्राइवेट शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान लाभ हेतु कार्य कर रहें है जहाँ अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है.
- सेल्फ फाइनेंस मूड में पाठ्यक्रम का चलना : देश भर के विभिन्न राज्यों के विश्विद्यालयों में अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम सेल्फ फाइनेंस मूड में चल रहा है जहाँ शिक्षकों एवं सम्बंधित कर्मियों को अनुबंध पर नियुक्ति की जाती है और दिहाड़ी के मजदुर के सामान काम करवाया जाता है और बदले में बहुत कम वेतन मिलता है.
- भयंकर स्तर पर व्याप्त भ्रस्टाचार: अध्यपक शिक्षा का कोर्स भयंकर भ्रस्टाचार में संलिप्त है, निजी संस्थानों के वर्चस्व के कारण मनमाने ढंग से मूल्यांकन हेतु पैसों का बंदरबांट होता है.
- शिक्षकों की दयनीय सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति: बहुत कम वेतन मिलने से शिक्षकों की स्थिति बहुत ख़राब होती है, भविष्य की सुरक्षा के अभाव में शिक्षक समुदाय आत्मविश्वास के साथ काम नहीं कर पाते हैं.
- सरकारी उदासीनता : 10-20 वर्षों से लगातार शिक्षकों को सेल्फ फाइनेंस मूड में काम कराना सरकारी उदासीनता को प्रदर्शित करता है.

- व्यवसायीकरण: निजी संस्थानों के अपेक्षाकृत अधिक वर्चस्व के कारण अध्यापक शिक्षा अधिक व्यावसायिक प्रकृति को हो गयी है जहाँ उच्च गुणवता के शिक्षकों का निर्माण रुक गया है.
- केंद्रीय अभिकरणों की बदहाल स्थिति : □□□□ का एक केन्द्रीय इकाई के रूप रूप में काम करने के तरीके, इसकी वस्तु स्थिति को लेकर भी हमेशा सवाल उठते रहे हैं □ देश में निजी अध्यापक शिक्षण संस्थानों की भरमार है परन्तु संख्या के रूप में शिक्षक तैयार तो हो रहें पर पेशेवर दक्षता एवं गुणवता में काफी कमजोर है □ जबकि □□□□ स्वयं सभी संस्थानों की मान्यता देती एवं समय समय पर पर्यवेक्षण करती है □ □□□□ मैं फैला भ्रस्टाचार ने निजी अध्यापक शिक्षण संस्थानों को अध्यापक शिक्षा को पूरी तरह एक व्यवसाय बनाने की खुली छुट मिल गयी है □ देश भर के अधिकांश सरकारी अध्यापक शिक्षण संस्थानों में ,विश्व विद्यालयों में अध्यापक शिक्षा से संबंधित विविध कोर्स सेल्फ फाइनेंस मूड में चल रही है जहाँ शिक्षकों को बहुत कम वेतन पर काम करना पड़ता है □ निजी अध्यापक शिक्षण संस्थानों में तो कागजो पर शिक्षकों की नियुक्ति होती और वे घोस्ट टीचर के रूप में अपनी सेवाएँ देते है □ रेगुलर रूप से कार्यरत शिक्षकों की संख्या बहुत कम होती है जिन्हें भी बहुत थोड़े वेतन में कम करना पड़ता □ स्वयं □□□□ जो अध्यापक शिक्षा से संबंधित विभिन्न कोर्स अपने केन्द्रीय एवं क्षेत्रिय केन्द्रों में कराती अध्यापकों अनुबध पर सेवाएँ ले रही है ये आपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है.

निष्कर्ष

नए बदलाव के साथ नई चुनौतियां तो आएँगी ही इसलिए चुनौतियों को कम कैसे किया जाय इस पर सार्थक कदम उठाया जाना चाहिए । केंद्र बनाम राज्य के बिच एवं सरकारी बनाम निजी के द्वन्द को समाप्त कर समन्वय स्थापित करना होगा । इसके सफल क्रियान्वयन के लिए एवं आने वाली चुनौतियों की सामना करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने के साथ इस पर गंभीरता पूर्वक काम करना होगा । बदले स्वरुप को स्थापित करने के लिए एवं नए संस्थानों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर जरुरत पड़ने वाली वित्त का भी प्रबंध करना होगा । नई शिक्षा नीति के अलोक में अध्यापक शिक्षा के अलग –अलग आयामों जैसे- शिक्षकों के निर्माण, निर्माण के लक्ष्य, गुणवता संवर्धन, भर्ती, पदस्थापन, कार्य संस्कृति, पाठ्यक्रम, पर्यवेक्षण, परिक्षण, गरिमा, सुरक्षा, वितीय प्रावधान आदि मसलों पर गभीरता से विचार किया जाना जरुरी है । शिक्षक शिक्षा से जुड़े संस्थान भी बदले स्वरूप में काम करेंगे। लेकिन शिक्षाविदों को शिक्षक शिक्षा से जुड़े बुनियादी सवालों का समाधान खोजना होगा ताकि राष्ट्रीय निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार किए जा सकें।

References

1. National Education Policy 2020, Ministry of Human Resource Development Government of India https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf.
2. Chanchal, Rajshree. (2021). New Education Policy 2020 and Teacher Education. 10. 365-363.
3. Srinivasan, S. (2015). Revamping Teacher Education. Economic and Political Weekly, Vol 35:22-24.
4. Gupta, Rupa. (2022). A Critical Study on New Education Policy-2020.
5. Kumar, Suman. (2021). New Education Policy 2020.
6. Kalgotra, Ritu. (2022). Implementing new education policy-2020.
7. Vyas, Devendra. (2022). New Education Policy – An Overview of Higher Education.
8. T.Sundararasan. (2022). Threats in New Education Policy 2020.

Corresponding Author
*** डॉ संजय कुमार**
विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग
चतरा कॉलेज,झरिया